

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022—ज्येष्ठ 13, शक 1944

## भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. D-1174,

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 सहपठित धारा 477 दं.प्र.सं., 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 1/2017 संदर्भ: आपराधिक विचारणों में कमियों और अपर्याप्तताओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने संबंधी पारित आदेश के अनुसरण में, एतद्वारा,

मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्;

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 107 के पश्चात् निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए, अर्थात्;

"108. अभियोजकों एवं अन्वेषकों का पृथक्करण—

अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार लोक अभियोजकों से भिन्न अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी।"

2. नियम 117 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्;

"117-क. धारा 173, 207 एवं 208 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत दस्तावेज प्रदान करना—

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 एवं 208 के अनुसार प्रत्येक अभियुक्त को द.प्र.सं. की धारा 161 एवं 164 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथन एवं अन्वेषण के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों की एक सूची, जिन पर अन्वेषण अधिकारी (आई.ओ.) निर्भर रहा है, प्रदाय किए जाएंगे।

**स्पष्टीकरण:—** कथनों, दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों की सूची उन कथनों, दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों को विनिर्दिष्ट करेगी जिन पर अन्वेषण अधिकारी निर्भर नहीं रहा है।

117-ख. जमानत—

(1) अजमानतीय मामलों में जमानत के लिए आवेदन सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तारीख से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर

निपटाए जाएंगे। यदि आवेदन ऐसी अवधि के भीतर निपटाया नहीं जाता है तो पीठासीन अधिकारी आदेश में ही उसके कारण देंगे। आदेश एवं जमानत आवेदन का उत्तर अथवा प्रास्थिति प्रतिवेदन (पुलिस या अभियोजन द्वारा) यदि कोई हो तो, की प्रति अभियुक्त को आदेश सुनाए जाने की तारीख को ही दी जाएगी।

(2) पीठासीन अधिकारी, किसी भी समुचित मामले में अपने स्वविवेकानुसार मामले के भारसाधक अभियोजक द्वारा कथन प्रस्तुत किए जाने पर जोर दे सकते हैं।”

3. नियम 170 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्;

“170-क. आरोप विरचित करने के आदेश के साथ दं.प्र.सं., 1973 की अनुसूची II के प्ररूप 32 में औपचारिक आरोप होगा जो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा संपूर्ण एवं पूर्ण रूप से बुद्धि का संपूर्ण एवं पूर्ण अनुप्रयोग करके व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाएगा।”

4. नियम 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 एवं 187 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्;

“180. प्रक्रिया—

(1) साक्षियों की अभिसाक्ष्य, यदि संभव हो तो, टंकित प्रारूप में अभिलिखित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी के बोलने पर न्यायालय में साक्ष्य का अभिलेख, यदि उपलब्ध हो तो कम्प्यूटर पर तैयार किया जाएगा। किसी मामले में, यदि टंकित प्रारूप में अभिसाक्ष्य को अभिलिखित करना संभव नहीं है तो साक्षी की अभिसाक्ष्य न्यायालय द्वारा उसकी स्वयं की हस्तलिपि में लिखी जाएगी।

परन्तु जब किसी मामले में अभिसाक्ष्य अंग्रेजी या राज्य की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अभिलिखित की जानी है, तो पीठासीन अधिकारी उसी समय या तो स्वयं या एक सक्षम अनुवादक के माध्यम से अभिसाक्ष्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे।

- (2) अभिसाक्ष्य को साक्षी की भाषा में और जब अनुवाद किया जाता है तो उपनियम (1) में यथाउपबंधित अंग्रेजी में अभिलिखित किया जाएगा।
- (3) अभिसाक्ष्यों को बिना किसी अपवाद के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा। इस प्रकार अभिलिखित की गई गवाही की हार्ड कॉपी, जिसे पीठासीन अधिकारी/न्यायालय अधिकारी द्वारा एक सत्यप्रतिलिपि के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, अभियुक्त या अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को, साक्षी को और अभियोजक को उसे अभिलिखित करने की तिथि पर, पावती लेकर, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- (4) पीठासीन अधिकारी एक ही समय पर एक से अधिक प्रकरणों में साक्ष्य अभिलिखित नहीं करेंगे।

**181.** प्रत्येक न्यायालय में एक अनुवादक उपलब्ध कराया जाएगा और पीठासीन अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं में, पीठासीन अधिकारी के निवेदन पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

यदि अनुवादक न्यायालय का कर्मचारी नहीं है या सरकार द्वारा नियुक्त अनुवादक नहीं है तो न्यायालय उसे उसकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत है, जो अर्धकुशल साक्षी को भुगतान किये गये डी ए की राशि से अधिक नहीं हो। इस खाते के प्रभार उसी मद के नामे डाले जाएंगे, जो साक्षी के खर्चे से संबंधित हो।

**182. साक्षियों के प्ररूप—**

- (1) अभिसाक्ष्य विहित प्रपत्र पर और प्रथम पुरुष में अभिलिखित किये जाएंगे।
- (2) प्रत्येक साक्षी की अभिसाक्ष्य, अलग-अलग पैराग्राफ में विभक्त कर पैरासंख्या देते हुए अभिलिखित की जायेगी।
- (3) अभियोजन साक्षियों को क्रमानुसार अ.सा. 1, अ.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा। इसी प्रकार बचाव साक्षियों को क्रमानुसार ब.सा. 1, ब.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया

जाएगा। न्यायालयीय साक्षियों को क्रमानुसार न्या.सा. 1, न्या.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

- (4) यदि अभिसाक्ष्य एक ही पत्रक में पूरा नहीं किया जा सके, तो इसे अगले पत्रक में जारी रखा जाना चाहिए। प्रथम अनुवर्ती पत्रक पर "2", दूसरे पर "3" और इसी प्रकार आगे की संख्या लिखी जाएगी। प्रत्येक पत्रक पर क्रमांक तथा अ.सा., ब.सा., न्या.सा. के रूप में संख्या इंगित करते हुए साक्षी का नाम होना चाहिए। प्रत्येक साक्षी का अभिसाक्ष्य पृथक-पृथक पत्रक पर और संहिता में विहित रीति में अभिलिखित किया जाना चाहिए। एक साक्षी का अभिसाक्ष्य विस्तारपूर्वक अभिलिखित करके और अन्य साक्षियों के नामों के सम्मुख यह प्रविष्ट करना कि वे "उपरोक्तानुसार कथन करते हैं" अवैध है।
- (5) अभिसाक्ष्य पत्रकों और अनुवर्ती पत्रकों, दोनों के शीर्षक निरपवाद रूप से पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं भरे जाने चाहिए। पूर्व दशा में, जब अपेक्षित हो, "प्रतिज्ञान" के स्थान पर शब्द "शपथ" स्थापित किया जाएगा। यदि साक्षी स्वयं की सही आयु बताने में समर्थ प्रतीत नहीं होता है तब शीर्षक में कथित आयु पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमानित की जाएगी। यदि, किसी विशेष कारण से, साक्षी का उसकी स्वयं की आयु के संबंध में कथन लिखा जाना आवश्यक हो, तो वह अभिसाक्ष्य के अंग के रूप में लिखा जाएगा। साक्षी का नाम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान एवं व्यवसाय की विशिष्टियां उसके अभिसाक्ष्य का ही भाग होते हैं और यह शपथ या प्रतिज्ञान दिलाए जाने तक अभिलिखित नहीं किए जाने चाहिए। साक्षी का व्यवसाय यथार्थता के साथ अभिकथित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए "नौकरी" पर्याप्त विवरण नहीं है, यह कथित होना चाहिए कि साक्षी किस प्रकार की नौकरी में है। इसी प्रकार, "निजी सेवा", जिसका तात्पर्य लोक-नियोजन के विपरीत निजी नियोजन से अधिक कुछ नहीं होता, इसे किसी विशिष्ट प्रकार के नियोजन के

रूप में विचारित किया जाना चाहिए। किसी साक्षी का व्यवसाय केवल शासकीय सेवक नहीं लिखा जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि सामान्यतः यह जानना उपयोगी होता है कि वह किस प्रतिष्ठा का है तथा कभी यह जानना विशेष महत्व का होता है कि क्या वह पुलिस अधिकारी है या नहीं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्थानीय रूप से विख्यात एक साक्षी न्यायालय में विख्यात नहीं भी हो सकता है, जिसके लिये अन्ततः अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साक्षी विवाहित स्त्री है तब उसके पिता के स्थान पर उसके पति का नाम लिखा जाना चाहिए।

- (6) अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय, बोलचाल की भाषा के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और यदि ऐसे शब्द आवश्यक हैं तो उनके निकटतम अर्थ को कोष्ठकों में बताया जाना चाहिए ताकि संदिग्धता से बचा जा सके। भारतीय तिथियों के बाद कोष्ठकों में उनके अंग्रेजी समकक्ष होने चाहिए।
- (7) यदि कोई साक्षी कुछ सीमा चिन्हों को दर्शाते हुए दूरी के संबंध में कथन करता है, तो पीठासीन अधिकारियों द्वारा अनुमानित दूरी अभिनिश्चित की जानी चाहिए तथा कोष्ठकों में उल्लिखित की जानी चाहिए।
- (8) पीठासीन अधिकारी को साक्षी की भाव-भंगिमा के संबंध में टिप्पणी देने में, जबकि ऐसी भाव-भंगिमा ध्यान देने योग्य है तथा साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य के मूल्यांकन में उसके अनुमान को प्रभावित करती है, चूक नहीं करनी चाहिए।
- (9) अभिसाक्ष्यों का अभिलेख मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं पुनः परीक्षण की तिथि उपदर्शित करेगा।
- (10) पीठासीन अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अभिसाक्ष्य को प्रश्न व उत्तर के रूप में अभिलिखित करेंगे।
- (11) अभियोजन अथवा बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा तथा उन्हें साक्ष्य में परिलक्षित किया जाएगा

तथा उन्हें यथाशीघ्र, विधि के अनुसार या विद्वान न्यायाधीश के विवेक पर, प्रश्नगत साक्षी की अभिसाक्ष्य की समाप्ति पर विनिश्चित किया जाएगा।

- (12) किसी पश्चातवर्ती तिथि पर साक्षी का नाम और क्रमांक स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा, यदि साक्ष्य उस तिथि पर समाप्त नहीं होती है जिस तारीख को वह आरंभ होती है।
- (13) प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य को, उस साक्षी को पढ़कर सुनाना चाहिए अथवा इसे स्वयं साक्षी द्वारा पढ़ा जा सकता है। प्रत्येक अभिसाक्ष्य को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित (ना केवल अद्योहस्ताक्षरित) किया जाना चाहिए, जिन्हें अपने हस्ताक्षर में कम से कम अपने अधिकारिक पदनाम को दर्शाने वाले आद्याक्षरों को जोड़ना चाहिए, ताकि अभिसाक्ष्य स्वयं में पूर्ण हो सके। प्रत्येक अभिसाक्ष्य पत्र साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित/अंगुष्ठ चिन्हित, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

**टिप्पणी:—** किसी अभिसाक्ष्य या न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख के भाग में किए गए प्रत्येक परिवर्तन, अंतरालेखन तथा मिटाए जाने को सदैव उसी समय पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अद्योहस्ताक्षरों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। वह अभिसाक्ष्यों या साक्ष्य के ज्ञापन को टंकित कर सकेगा किंतु वह ऐसी टंकित विषयवस्तु के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करेगा।

- (14) प्रत्येक अभिसाक्ष्य के अंत में, पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में एक प्रमाणपत्र अनुलग्नित किया जाएगा:—  
"मेरे द्वारा न्यायालय में लिखा गया या लिखवाया गया तथा साक्षी द्वारा समझा/पढ़ा गया अथवा साक्षी को समझाया/पढ़कर सुनाया गया।"
- (15) यदि साक्षी अभिलेख की शुद्धता स्वीकार करता है, अथवा जब कोई आवश्यक शुद्धियां की गई हैं, तब पीठासीन अधिकारी को अभिसाक्ष्य के पाद भाग पर अलग से उपयुक्त पृष्ठांकन करके तथा हस्ताक्षरित करके उसे प्रमाणित करना चाहिए। यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग

की शुद्धता उस समय अस्वीकार करता है जब ऐसा भाग उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तब पीठासीन अधिकारी अभिलेख में सुधार करने के बजाए, साक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का उस पर ज्ञापन बना सकेगा एवं ऐसी विशिष्टियां जोड़ेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

**183. श्रव्य-दृश्य संपर्क के माध्यम से साक्ष्य का अभिलेखन—**

साक्ष्य का श्रव्य-दृश्य संपर्क के माध्यम से अभिलेखन इस संबंध में पृथक रूप से बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

**टिप्पणी:** वर्तमान में "मध्यप्रदेश जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020" दिनांक 20.11.2020 को राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं।

**184. आवश्यक वस्तुओं एवं साक्ष्य का प्रदर्शित किया जाना—**

(1) अभियोजन प्रदर्श पी 1, पी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हांकित किए जाएंगे। समानतः, प्रतिरक्षा प्रदर्श, प्रदर्श डी 1, डी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हित किए जाएंगे। न्यायालय प्रदर्श, प्रदर्श सी 1, सी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हित किए जाएंगे।

(2) उस साक्षी का आसानी से पता लगाने के लिए, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, प्रदर्श क्रमांक आगे, प्रदर्श संख्या के पश्चात् ऐसे साक्षी की साक्षी संख्या दर्शित करेंगे। यदि कोई प्रदर्श, बिना उचित प्रमाण के चिन्हित किया गया है, तो उसे कोष्ठक में (प्रमाण के अधधीन) दिखाकर दर्शाया जावेगा।

**स्पष्टीकरण:** यदि अभियोजन साक्षी क्र. 1 (अ.सा. 1) साक्ष्य में कोई प्रलेख प्रस्तुत करता है, तो उस प्रलेख को प्रदर्श पी 1/अ.सा. 1 चिन्हित किया जाएगा। यदि उस प्रलेख को चिन्हांकित किए जाने के समय उसके लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे प्रदर्श पी 1/अ.सा. 1 (प्रमाण के अधधीन) चिन्हांकित किया जाएगा। अ.सा. 1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रलेख प्रदर्श पी. 2/ अ.सा. 1 होगा।



- (3) आवश्यक वस्तुएं क्रमानुसार आ.व. 1, आ.व. 2 इत्यादि के रूप में चिन्हित की जाएंगी।

**185. अभियुक्त, साक्षी, प्रदर्शों तथा आवश्यक वस्तुओं का पश्चात्वर्ती उद्धरण—**

- (1) आरोप विरचना के पश्चात्, अभियुक्तों को आरोप में अभियुक्त श्रृंखला में उनकी रैंक व उनके नाम अथवा अन्य संदर्भों से संदर्भित किया जाएगा।
- (2) साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने, प्रदर्श व आवश्यक वस्तुओं को चिन्हित करने के पश्चात्, अन्य साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान, साक्षीगण, प्रदर्श व आवश्यक वस्तुएं उनके क्रमांक से संदर्भित की जाएंगीं ना कि उनके नामों या अन्य संदर्भों से।
- (3) जहां शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उद्धरित साक्षियों का परीक्षण नहीं हुआ है, वे उनके नामों व शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उन्हें आबंटित संख्या से संदर्भित किये जाएंगे।

**186. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व 164 के अंतर्गत कथन संबंधी उद्धरण—**

- (1) प्रतिपरीक्षण के दौरान संबंधित साक्षी का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किये गये धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दर्ज बयान के सुसंगत हिस्से को उद्धृत किया जाएगा। यदि उपरोक्तानुसार सुसंगत अंश उद्धृत किया जाना संभव न हो, तो पीठासीन अधिकारी, अपने स्वविवेक से, ऐसे सुसंगत अंश के प्रारंभिक व अंतिम शब्दों को, पृथक अंकन के माध्यम से, अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय विनिर्दिष्टतः दर्शायेगा।
- (2) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत अंश उद्धृत नहीं किया जाता है, केवल अंशों को ही अभियोजन या बचाव प्रदर्श के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, स्पष्टतः चिन्हित किया जाएगा, ताकि साक्ष्य के अन्य अग्राह्य भाग अभिलेख का हिस्सा न हो।

- (3) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत अंश उद्धृत नहीं किया जाता, वहां ग्राह्य भाग को स्पष्टतः अभियोजन अथवा बचाव प्रदर्श के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, चिन्हित किया जाएगा।
- (4) जब कभी जीवित व्यक्तियों के पूर्व कथनों के ऐसे अंश विरोधाभास/संपुष्टि हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, तब धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों पर लागू होने वाले पूर्वोक्त नियम, द.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित किए गये कथनों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (5) द.प्र.सं. की धारा 161 व 164 के अधीन संपूर्ण कथन का सर्वव्यापक अंकन नहीं किया जाएगा।

#### 187. संस्वीकृति कथनों का चिन्हांकन—

पीठासीन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 अथवा धारा 27 के अधीन ज्ञापन का प्रदर्श चिन्हित करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे ज्ञापन के ग्राह्य भाग को चिन्हित किया गया है तथा ऐसे भाग को एक पृथक पृष्ठ पर निकाला गया है तथा चिन्हित किया गया है और एक प्रदर्श संख्या दी गई है।”

5. नियम 189 का लोप किया जाए।

6. नियम 191 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

#### \*191. शीघ्र विचारण हेतु निर्देश—

- (1) प्रत्येक जांच व विचारण में, कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से की जाएंगी, एवं, विशेष रूप से, जब एक बार साक्षियों का परीक्षण आरंभ हो गया है, तो वे सभी हाज़िर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। (द.प्र.सं., 1973 की धारा 309(1))। इस प्रयोजनार्थ, प्रारंभ में एवं आरोप की विरचना के तत्काल बाद, न्यायालय यह ध्यान में रखकर कि क्या साक्षी महत्वपूर्ण हैं अथवा

चक्षुदर्शी साक्षी हैं, अथवा औपचारिक साक्षी हैं अथवा विशेषज्ञ हैं, साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु लगातार तारीखों को सुनिश्चित करने व नियत करने के लिए समयबद्ध सुनवाई आयोजित करेगा, न्यायालय तब ऐसी निरंतर तारीखों को दर्शित करते हुए एक कार्यक्रम बनाएगा, जब साक्षियों का परीक्षण किया जाएगा; यह किसी एक दिनांक को साक्षियों के एक समूह की, अगली दिनांक को अन्य समूह की और इसी तरह आगे, अभिसाक्ष्यों के अभिलेखन का कार्यक्रम बनाने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय, विचारण आरंभ होने के पूर्व, यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्या पक्षकार द.प्र.सं., 1973 की धारा 294 के अंतर्गत किसी दस्तावेज को स्वीकृत कराना चाहते हैं एवं उन्हें ऐसा करने की अनुज्ञा देगा, जिसके पश्चात् विचारण हेतु ऐसी लगातार तारीखें नियत की जाएंगी।

- (2) विचारण के आरंभ होने के पश्चात्, यदि न्यायालय यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का आरंभ करना मुलतवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो वह समय-समय पर, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिए जितना वह युक्तियुक्त समझे, उसे मुलतवी या स्थगित कर सकेगा। यदि साक्षी हाजिर हों तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नहीं दी जाएगी। (द.प्र.सं. 1973 की धारा 309(2))
- (3) सत्र मामलों को अन्य कार्यों से अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है एवं जब तक किसी दिन कोई सत्र कार्य पूर्ण नहीं होता, तो सत्र दिनों में कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। जब एक बार कोई सत्र मामला नियत किया जाता है, तो जब तक अपरिहार्य ना हो, उसे मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए, और जब एक बार विचारण प्रारंभ हो चुका है तो इसके पूर्ण होने तक इसे दिन-प्रतिदिन जारी रखना चाहिए। यदि किसी कारण से, किसी मामले को स्थगित या मुलतवी

करना हो तो दोनों पक्षों को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए तथा साक्षियों को रोकने एवं स्थगित तारीख पर उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।”

7. नियम 238 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्;

“238-क. प्रत्येक निर्णय में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे—

- (1) नियमों के प्ररूप-घ के अनुसार पक्षकारों के नाम दर्शित करने वाली प्रस्तावना से शुरुआत।
- (2) नियमों के प्ररूप-ड. के अनुसार सारणीबद्ध विवरण।
- (3) नियमों के प्ररूप-च के अनुसार अभियोजन साक्षी, बचाव साक्षी, न्यायालय साक्षी, अभियोजन प्रदर्श, बचाव प्रदर्श, न्यायालय प्रदर्श एवं आवश्यक वस्तुओं की सूची देते हुए परिशिष्ट।

238-ख. द.प्र.सं., 1973 की धारा 354 एवं 355 के अनुपालन में, समस्त मामलों में निर्णय में अंतर्विष्ट होंगे:

- क. अवधारण के लिए एक या अधिक प्रश्न,
- ख. उन पर विनिश्चय, एवं
- ग. विनिश्चय का कारण।”

8. नियम 240 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

“240(1) निर्णय युक्तियुक्त लंबाई के पदों में लिखा जायेगा और प्रत्येक पद को क्रमानुसार संख्यांकित किया जायेगा। यथाविधि वे नियत टंकित पृष्ठ के लगभग तीन चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उनका उपपदों में विभाजन करने से बचा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी, अपने स्वविवेक से, निर्णय को विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह मुख्यतः अपीलीय अथवा पुनरीक्षण की न्यायालय में तर्क के दौरान, निर्णय के किसी विशेष भाग के उल्लेख को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं।

- (2) प्रारंभिक पदों में कमोवेश आरोप के विवरण देते हुए संक्षेप में यह बताया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति पर क्या करने का आरोप है, जिससे कि प्रारंभ से ही यह बात पता लग जाए कि निर्णय किस बारे में है।
- (3) अगले एक या दो पदों में स्वीकृत/अविवादित तथ्य दिये जाने चाहिए और अभियोजन मामले तथा प्रतिरक्षा के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर करते हुए संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए कि क्या स्वीकृत/अविवादित है और क्या नहीं। ग्रामों तथा स्थानों की दशा, उनके मध्य की दूरी एवं पक्षकारों एवं साक्षियों के आपसी संबंध जैसे विषयों का संकेत किया जाना चाहिए, जब ऐसे विवरण ऐसे मामलों को स्पष्टतः समझने के लिए आवश्यक हों।
- (4) उसके पश्चात् पक्ष एवं विपक्ष के साक्ष्य को क्रमबद्ध करते हुए एवं तर्क पर विचार करते हुए और दूसरे बिंदु पर अग्रसर होने के पूर्व पहले बिंदु पर स्पष्ट निष्कर्ष देते हुए जो बिंदु निर्णय के लिए उठते हैं उन्हें एक के बाद एक उल्लिखित करना चाहिए। विभिन्न बिन्दुओं को पृथक-पृथक पदों में अभिलिखित किए जाना चाहिए किंतु कुछ बिन्दुओं के लिए एक से अधिक पदों की आवश्यकता पड़ सकती है। उद्देश्य के प्रश्न पर पहले विचार करना अनुचित है, क्योंकि वह ऐसे तर्क को आमंत्रित करता है कि एतद्वारा न्यायालय मामले के गुणदोषों का पूर्व से ही निर्णय कर लेती है।
- (5) स्पष्ट एवं अविवादित बिन्दु पर श्रम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि एक व्यक्ति का सिर उसके शरीर से लगभग अलग हो गया है तो इस साक्ष्य पर विवेचन करना कभी-कभी ही आवश्यक हो सकता है कि वह व्यक्ति उसके बहुत पहले स्वस्थ नहीं था; उसकी चोटों की प्रकृति को इंगित करना और यह कहना कि यह स्पष्ट है और विवादित नहीं रहा है कि उसकी हत्या की गई थी, सामान्यतः पर्याप्त होगा और कि विनिश्चय के लिए केवल प्रश्न यह है कि उसकी किसने हत्या की।

- (6) विनिश्चय हेतु उत्पन्न समस्त बिन्दुओं के विनिश्चय के पश्चात् सम्पूर्ण मामले का निर्णय उसी अथवा आगामी पद में दंडादेश, यदि कोई हो, सहित होगा। यदि अभियुक्त द्वारा एक से अधिक अपराध किया जाना पाया जाता है तब प्रत्येक अपराध के किये पृथक दंडादेश जब तक कि उससे भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का अतिलंघन न होता हो, पारित किया जाना चाहिए, किंतु ऐसे दंडादेश समवर्ती रूप से चल सकेंगे।
- (7) न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट को निर्णय का लेखन तब तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने मस्तिष्क में यह स्पष्ट नहीं कर लेता है कि कौन-कौन से बिन्दु पर उसे विनिश्चय करना है, उनका वह किस प्रकार निर्णय करने जा रहा है, और उनके निष्कर्षों के क्या कारण हैं तब वह इन बिन्दुओं की, जहां तक संभव हो, स्पष्ट और संक्षिप्त चर्चा करेगा। निर्णय जब तक बाद में सतर्कतापूर्वक पढ़ा नहीं जाता और जहां आवश्यक हो सुधारा नहीं जाता, तब तक उसका पूरी तरह स्पष्ट होना असंभावित है।
- (8) ये टिप्पणियां मुख्यतः विचारण न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए आशयित हैं, किन्तु सामान्य सिद्धांत अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी ध्यान में रखे जाना चाहिए।”

9. नियम 243 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

- “243. (1) निर्णय में अभियुक्त, साक्षीगण, प्रदर्श तथा आवश्यक वस्तुओं को उनके नामपद्धति अथवा संख्या द्वारा संदर्भित किया जाएगा और न केवल उनके नाम से या अन्यथा। जहां कहीं भी, अभियुक्त अथवा साक्षियों को उनके नाम से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता हो, संख्या को कोष्ठक में उपदर्शित किया जाएगा।
- (2) दोषसिद्धि के मामले में, अंतर्ग्रस्त अपराध एवं दी गई सजा को निर्णय में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। यदि कई अभियुक्तगण हैं, तो उनमें से प्रत्येक के बारे में पृथक से कार्यवाही की जाएगी। दोषमुक्ति के

मामले में एवं यदि अभियुक्त परिरोध में है, तो अभियुक्त को मुक्त करने के लिए निर्देश दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियुक्त किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में न हो।”

10. नियम 458 में, अंतिम दो पैराग्राफ लोप किये जाएं।

11. प्ररूप—ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएं, अर्थात्;

प्ररूप—घ

<p>समक्ष न्यायालय: .....</p> <p>समक्ष ..... सत्र न्यायाधीश</p> <p>[निर्णय की तारीख]</p> <p>[प्रकरण सं. .... / 20.....]</p> <p>(प्र.सू.रि./ अपराध और पुलिस थाने का विवरण)</p>	
परिवादी	राज्य ..... या परिवादी का नाम
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता का नाम
अभियुक्त	(1) नाम सभी विशिष्टियों सहित (अ 1) (2) नाम सभी विशिष्टियों सहित (अ 2)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्तागण का नाम

## प्ररूप—ड.

अपराध की तारीख	
प्र.सू.रि. की तारीख	
आरोप-पत्र की तारीख	
आरोपों के विरचना की तारीख	
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	
निर्णय की तारीख	
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	

## अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि

## प्ररूप—च

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय



		साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1		
अ.सा. 2		

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो: -

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा. 1		
ब.सा. 2		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो: -

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा. 1		
न्या.सा. 2		

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1/ अ.सा. 1	
2	प्रदर्श पी. 2/ अ.सा. 2	

## ख. प्रतिरक्षा :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी. 1/ब.सा. 1	
2	प्रदर्श डी. 2/ब.सा. 2	

## ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी. 1/ न्या.सा. 1	
2	प्रदर्श सी. 2/ न्या.सा. 2	

## घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आ.व. 1	
2	आ.व. 2	

\*\*\*\*\*

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 19<sup>th</sup> May 2022

No. D-1174.

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 477 of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal) in pursuance to order passed by the Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition (Crl.) No. 1/2017 In Re: To Issue Certain Guidelines Regarding Inadequacies and Deficiencies in Criminal Trials.

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After Rule 107, the following rule shall be added, namely;

**“108. Separation of prosecutors and investigators-**

The State Governments shall appoint advocates, other than Public Prosecutors, to advise the Investigating Officer during investigation.”

2. After rule 117, the following rules shall be added, namely;

**“117-A. Supply of documents under sections 173, 207 and 208 of Cr.P.C., 1973-**

Every Accused shall be supplied with statements of witness recorded under Sections 161 and 164 Cr.P.C., 1973 and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (I.O) in accordance with Sections 207 and 208, Cr.P.C., 1973.

**Explanation:** The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.

**117-B . BAIL-**

(1) The application for bail in non-bailable cases must ordinarily be disposed off within a period of 3 to 7 days from the date of first hearing. If the application is not disposed off within such period, the Presiding Officer shall furnish reasons thereof in the order itself. Copy of the order and the reply to the bail application or status report (by the police or prosecution) if any, shall be furnished to the accused on the date of pronouncement of the order itself.

(2) The Presiding Officer may, in an appropriate case in its discretion insist on a statement to be filed by the prosecutor in charge of the case.”

3. After rule 170, the following rule shall be added, namely;

“170-A. The order framing charge shall be accompanied by a formal charge in Form 32; Schedule II, Cr.P.C., 1973 to be prepared personally by the Presiding Officer after complete and total application of mind.”

4. For rule 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 and 187, the following rules shall be substituted, namely;

**“180 . Procedure-**

(1) The depositions of witnesses shall be recorded, in typed format, if possible. The record of evidence shall be prepared on computers, if available, in the Court on the dictation of the Presiding Officer. In case, if recording of deposition in typed format is not possible then the deposition of the witness will be taken down by the Court in his/her own handwriting.

Provided that in case the language of deposition is to be recorded in a language other than English or the language of the State, the Presiding Officer shall simultaneously translate the deposition either himself or through a competent translator into English.

- (2) The deposition shall be recorded in the language of the witness and in English when translated as provided in sub-rule (1).
- (3) The depositions shall without exception be read over by the Presiding Officer in Court. Hard copy of the testimony so recorded duly signed to be a true copy by the Presiding Officer / Court officer shall be made available free of cost against receipt to the accused or an advocate representing the accused, to the witness and the prosecutor on the date of recording.
- (4) The Presiding Officers shall not record evidence in more than one case at the same time.

**181.** A translator shall be made available in each Court and Presiding Officers shall be trained in the local languages, on the request of the Presiding Officer.

In case, the translator is not an employee of the Court or is not a Government translator, the Court is authorized to pay him a reasonable remuneration for his services not exceeding the amount of DA paid to semi-skilled witness. The charges on this account shall be debited to the same head, which relates to the expenses of witness.

**182. Format of Witnesses -**

- (1) Depositions shall be recorded on the prescribed proforma and in first person.
- (2) The deposition of each witness shall be recorded dividing it into separate paragraphs assigning paragraph numbers.
- (3) Prosecution witnesses shall be numbered as PW-1, PW-2 etc, in seriatim. Similarly, defence witnesses shall be numbered as DW-1, DW-2, etc, in seriatim. The Court witnesses shall be numbered as CW-1, CW-2, etc, in seriatim.
- (4) If the deposition cannot be completed in one sheet, it should be continued in next sheet. The first continuation sheet will be marked as "2", the second "3", and so on. Each sheet should bear the number and name of witness indicated the number as PW, DW, CW. The deposition of each witness should be recorded on a separate sheet and in the manner prescribed in the Code. It is illegal to record the deposition of one witness at length and to enter against the names of other witnesses that they "state as above".
- (5) The headings, both of deposition sheets and of continuation sheets are invariably to be filled-up by the presiding officer himself, In the former, the word "oath" will be substituted, when required, for "affirmation". If the witness does not appear to be able to state his own age correctly, the age of the witness stated in the heading will be estimated by the presiding officer. If, for an special reason, it is necessary to record the witness's own statement as to his age, it will be recorded in the body of the deposition. The particulars as to the name, parentage,

residence and occupation of the witness are a part of the deposition itself and are not to be recorded till the oath or affirmation has been administered. The occupation of the witness must be stated with precision. For instance, "servant" is not a sufficient description, it must be stated what kind of servant the witness is. Similarly, "private service", which means nothing more than private employment as opposed to public employment, must be resolved into a particular kind of employment. A witness should not be recorded as by occupation a Government servant, for it is generally useful to know of what standing he is and it is particularly important some times to know whether he is a police officer or not. It should be borne in mind that a witness well known locally may not be well known in the court to which the record may ultimately have to be submitted. If the witness is a married woman her husband's name should replace that of her father.

- (6) While recording depositions, use of colloquial words should be avoided and if such words are necessary then their nearest meaning should be stated in brackets so as to avoid any ambiguity. Indian dates should be followed their English equivalents in brackets.
- (7) If a witness makes statement about distance by indicating some landmarks, then approximate distance should be ascertained and mentioned in brackets by the Presiding Officers.
- (8) The presiding officer should not omit to make a note about the demeanour of a witness when such demeanour

is noteworthy and affects his estimate of the value of the evidence given by the witness.

- (9) The record of depositions shall indicate the date of the chief examination, the cross examination and re-examination.
- (10) The Presiding Officers shall wherever necessary record the deposition in question and answer format.
- (11) Objections by either the prosecution or the defence counsel shall be taken note of and reflected in the evidence and decided immediately, in accordance with law, or, at the discretion of the learned Judge, at the end of the deposition of the witness in question.
- (12) The name and number of the witness shall be clearly stated on any subsequent date, if the evidence is not concluded on the date on which it begins.
- (13) The evidence of each witness should be read over to the witness or it may be read by the witness himself. Each deposition should be signed (not merely initialled) by the presiding officer, who should add to his signature at least the initials indicating his official designation, so that the deposition may be complete in itself. Each deposition sheet shall also be signed/ thumb impressed, as the case may be, by the witness.

**Note:** Every alteration, interlineations and erasure made in any deposition or part of a record of judicial proceedings shall invariably be attested at the time by initials of the presiding officer. He may type depositions or memoranda of evidence, but he shall sign every page of such typed matter.



- (14) At the end of every deposition, a certificate by the Presiding Officer be appended in the following manner:  
“Taken down or dictated by me in court and interpreted/read over to or by the witness”.
- (15) If the witness admits the correctness of the record, or when any necessary corrections have been made, the presiding officer should certify to this effect by making and separately signing a suitable endorsement at the foot of the deposition. If the witness denies the correctness of any part of the evidence when the same is read over to him, the Presiding Judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary.

**183. Recording of evidence through audio-visual linkage-**

Recording of Evidence through Audio-Visual Linkage will be in accordance with the separate Rules framed in this regard.

**Note:** Presently, “The District Courts of Madhya Pradesh Video Conferencing and Audio-Visual Electronic Linkage Rules, 2020” has been notified in Gazette on 20.11.2020.

**184. Exhibiting of Material Objects and Evidence-**

- (1) Prosecution exhibits shall be marked as Exhibit P-1, P-2 etc *in seriatim*. Similarly, defence Exhibits shall be marked as Exhibit D-1, D-2, etc *in seriatim*. The Court exhibit shall be marked as Exhibit C-1, C-2, etc *in seriatim*.

- (2) To easily locate the witness through whom the document was first introduced in evidence, the exhibit number shall further show the witness number of such witness after the Exhibit number. If an exhibit is marked without proper proof, the same shall be indicated by showing in brackets (subject to proof).

**Explanation:** If Prosecution witness No.1 (PW-1) introduces a document in evidence, that document shall be marked as Exhibit P-1/PW-1. If proper proof is not offered for that document at the time when it is marked, it shall be marked as Exhibit P-1/PW-1 (subject to proof). The Second document introduced by PW-1 shall be Exhibit P-2/PW-1.

- (3) The Material objects shall be marked *in seriatim* as MO-1, MO-2 etc.

**185. Subsequent references to Accused, Witness, Exhibits and Material Objects-**

- (1) After framing of charges, the accused shall be referred to by their ranks in the array of accused in the charge and by their names or other references.
- (2) After recording the deposition of witnesses, marking of the exhibits and material objects, while recording deposition of other witnesses, the witnesses, exhibits and material objects shall be referred by their numbers and not by names or other references.
- (3) Where witness cited in the complaint or police report are not examined, they shall be referred to by their names and the numbers allotted to them in the complaint or police report.

**186. References to statements under section 161 and 164 Cr.P.C.-**

- (1) During cross examination, the relevant portion of the statements recorded under Section 161 Cr.P.C., used for contradicting the respective witness shall be extracted. If it is not possible to extract the relevant part as aforesaid, the Presiding Officer, in his discretion, shall indicate specifically the opening and closing words of such relevant portion, while recording the deposition, through distinct marking.
- (2) In such cases, where the relevant portion is not extracted, the portions only shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be, so that other inadmissible portions of the evidence are not part of the record.
- (3) In cases, where the relevant portion is not extracted, the admissible portion shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be.
- (4) The aforesaid rule applicable to recording of the statements under Section 161 shall *mutatis mutandis* apply to statements recorded under Section 164 of the Cr.P.C, whenever such portions of prior statements of living persons are used for contradiction/ corroboration.
- (5) Omnibus marking of the entire statement under section 161 and 164 Cr.P.C shall not be done.

**187. Marking of Confessional Statements-**

The Presiding Officer in addition to marking exhibit of Memo under section 8 or section 27 of the Indian

Evidence Act, 1872 shall also ensure that admissible portion of such Memo is marked and such portion is extracted on a separate sheet and marked and given an exhibit number.

5. Rule 189 shall be omitted.
6. For Rule 191, the following rule shall be substituted, namely;

**“191. Directions for Expeditious Trial-**

- (1) In every enquiry or trial, the proceedings shall be held as expeditiously as possible, and, in particular, when the examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded. (Section 309 (1) Cr.P.C.,1973). For this purpose, at the commencement, and immediately after framing charge, the court shall hold a scheduling hearing, to ascertain and fix consecutive dates for recording of evidence, regard being had to whether the witnesses are material, or eye witnesses, or formal witnesses or are experts. The court then shall draw up a schedule indicating the consecutive dates, when witnesses would be examined; it is open to schedule recording of a set of witness' depositions on one date, and on the next date, other sets, and so on. The court shall also, before commencement of trial, ascertain if the parties wish to carry out admission of any document under section 294 Cr.P.C., 1973 and permit them to do so, after which such consecutive dates for trial shall be fixed.

- (2) After the commencement of the trial, if the court finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable. If witnesses are in attendance no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded, in writing. (Section 309 (2) Cr.P.C.,1973).
- (3) Sessions cases may be given precedence over all other work and no other work should be taken up on session's days until the sessions work for the day is completed. A Sessions case once posted should not be postponed unless that is unavoidable, and once the trial has begun, it should proceed continuously from day today till it is completed. If for any reason, a case has to be adjourned or postponed, intimation should be given forthwith to both sides and immediate steps be taken to stop the witnesses and secure their presence on the adjourned date.”

7. After Rule 238, the following rules shall be added, namely;

**“238-A. Every judgment shall contain the following-**

- (1) Start with a preface showing the names of parties as per Form-D to the rules.
- (2) A tabular statement as per Form-E to the rules.
- (3) An appendix giving the list of prosecution witnesses, defence witnesses, Court witnesses, Prosecution Exhibits, Defence Exhibits and Court Exhibits and Material Objects as per Form-F to the Rules.

**238-B.** In compliance with section 354 and 355 Cr.P.C., 1973, in all cases, the judgments shall contain:

- A. the point or points for determination,
- B. the decision thereon, and
- C. the reasons for the decision”

**8.** For rule 240, the following rule shall be substituted, namely;

- “**240.** (1) A judgment shall be written in paragraphs of a reasonable length and each paragraph shall be numbered *in seriatim*. They should not as a rule exceed about three quarters of a typed page and their division into sub-paragraphs should be avoided. The Presiding Officers, may, in their discretion, organize the judgment into different sections. This is mainly to facilitate reference to any particular portion of the Judgment during the argument in the appellate or revisional court.
- (2) The opening paragraph should state briefly who is accused of doing what, giving more or less the details in the charge, so that it can be readily gathered from the start what the judgment is about.
- (3) The next paragraph or two paragraphs should give the admitted/undisputed facts and state briefly the prosecution case and the defence, clearly distinguishing between what is admitted/ undisputed and what is not. Matters like the relative position of places and villages and distances between them and how the parties and witnesses are related to each other

should be indicated where such details are necessary for a clear understanding of the case.

- (4) Then the points that arise for decision should be dealt with one by one, marshalling the evidence for and against and considering the arguments and giving a clear finding on one point before passing on to the next. The various points should be dealt with in separate paragraph, but some points may require more than one paragraph, it is inadvisable to consider the question of motive first, as that tends to invite the argument that the court thereby pre-judges the merits of the case.
- (5) A point that is obvious and undisputed should not be laboured. For example, if a man is found with his head almost severed from his body, it can seldom be necessary to discuss the evidence that he was hale not long before; it will generally be sufficient to indicate the nature of his injuries and to say that it is obvious and has not been disputed that he was murdered, and that the only question for decision is who murdered him.
- (6) After all the points that arise for decision have been decided the decision on the case as a whole will follow with the punishment, if any, either in the same or next paragraph. If the accused is found to have committed more than one offence, separate sentences should be passed for each offence, unless it infringes section 71

of the Indian Penal Code, but the sentences may of course run concurrently.

- (7) A judge or magistrate should not start to write a Judgment until he has got it clear in his own mind what points he has to decide, how he is going to decide them, and the reasons for his decisions. Then he should try to deal with these points as lucidly and concisely as possible. A Judgment is unlikely to be lucid throughout unless it is carefully read over afterwards and corrected where necessary.
- (8) These remarks are intended primarily for the guidance of trial courts, but the general principles should be borne in mind by appellate and revisional courts.”

9. For rule 243, the following rule shall be substituted, namely;

“243. (1) In the judgment, the accused, witnesses, exhibits and material objects shall be referred to by their nomenclature or number and not only by their names or otherwise. Wherever, there is a need to refer to the accused or witnesses by their name, the number shall be indicated within brackets.

- (2) In case of conviction, the judgment shall separately indicate the offence involved and the sentence awarded. In case there are multiple accused, each of them shall be dealt with separately. In case of acquittal and if the accused is in confinement, a direction shall be given to set the accused at liberty, unless such accused is in custody in any other case.”



10. In Rule 458, last two paragraphs shall be deleted.
11. After Form-C, the following forms shall be added, namely;

**Form -D**

<p>IN THE COURT OF .....</p> <p>Present ..... Sessions Judge</p> <p>[Date of the Judgment]</p> <p>[Case No...../20.....]</p> <p>(Details of FIR/Crime and Police Station)</p>	
COMPLAINANT	STATE OF .....
	OR
	NAME OF THE COMPLAINANT
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATE
ACCUSED	1. NAME WITH ALL PARTICULARS (A1) 2. NAME WITH ALL PARTICULARS (A2)
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATES



**FORM -F**

List of Prosecution/Defence/Court Witnesses

**A. Prosecution**

<b>RANK</b>	<b>NAME</b>	<b>NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)</b>
PW1		
PW2		

**B. Defence Witnesses, if any:**

<b>RANK</b>	<b>NAME</b>	<b>NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)</b>
DW1		
DW2		

**C. Court Witnesses, if any:**

<b>RANK</b>	<b>NAME</b>	<b>NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)</b>
CW1		
CW2		

## List of Prosecution/Defence/Court Exhibits

**A. Prosecution:**

Sr.No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1/PW 1	
2	Exhibit P-2/PW 2	

**B. Defence**

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1/DW 1	
2	Exhibit D-2/DW 2	

**C. Court Exhibits**

Sr.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit C-1/CW 1	
2	Exhibit C-2/CW 2	

**D. Material Objects:**

Sr.	Material Object Number	Description
1	MO1	
2	MO2	

By order of the Hon'ble Chief Justice,  
KRISHNAMURTY MISHRA, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. D-1176,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 122 एवं मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, सिविल अपील क्रं० 2021 का 1659 - 1660 / विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 7965 - 7966/2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देश दिनांक 22.04.2021 के अनुसरण में मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 138 के उप-नियम (1) में, प्रारंभ में शब्द, क्रमांक तथा अक्षरों "आदेश 10 नियम 1 प्रावधानों की ओर जो कदाचित ही पालन किए जाते हैं की ओर पीठासीन न्यायाधीशों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, क्रमांक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

"कब्जा देने से संबंधित वादों में, न्यायालय को तीसरे पक्ष के हित के संबंध में आदेश 10 के अंतर्गत वाद के पक्षकारों की परीक्षा करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 नियम 1 के उपबंधों का पालन करेंगे।"

2. नियम 143 में,-

(1) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(1-क) कब्जा देने से संबंधित वादों में, न्यायालय को आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पक्षकारों को शपथ पर, ऐसे दस्तावेज प्रकट एवं पेश करने के लिए कहा

जाए, जो पक्षकारों के कब्जे में हों, जिसमें ऐसी संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा शामिल है।”।

(2) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(2-क) आदेश 10 के अंतर्गत पक्षकारों की परीक्षा या आदेश 11 के अंतर्गत दस्तावेज की प्रस्तुति या कमीशन की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, न्यायालय को वाद के सभी आवश्यक या उचित पक्षकारों को जोड़ना चाहिए जिससे कार्यवाहियों की बहुलता से बचा जा सके एवं ऐसे वाद हेतुकों का संयोजन भी उसी वाद में करना चाहिए।”।

(3) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(5) धन के संदाय के लिए वाद में, विवादकों के स्थिरीकरण के पूर्व, प्रतिवादी जहाँ तक उसे वाद में उत्तरदायी बनाया जा रहा है, उस सीमा तक अपनी संपत्ति को शपथ पर प्रकट करने हेतु अपेक्षित किया जा सकेगा। न्यायालय इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रक्रम पर, समुचित मामलों में, वाद लंबित रहने के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत शक्तियों को उपयोग करते हुए, किसी आज्ञाप्ति की संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति अपेक्षित कर सकती है।”।

3. नियम 168 में, विद्यमान पैराग्राफ उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

- “(2) न्यायालय को, किसी संपत्ति के कब्जे के परिदान के संबंध में आज्ञाप्ति पारित करने के पूर्व आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज्ञाप्ति न केवल उस संपत्ति का स्पष्ट विवरण समाहित करे, बल्कि संपत्ति की स्थिति के संबंध में भी असंदिग्ध हो।”।
4. नियम 184 में, उप-नियम (1) के अंत में, शब्दों “वाद का निराकरण यथासम्भव शीघ्र हो जाए।” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
“वे प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक से छः माह के भीतर निराकृत हो जाएं, जिसे केवल लिखित में, ऐसे विलंब के कारणों को अभिलिखित करने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।”।
5. नियम 187 में, विद्यमान पैराग्राफ, उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—  
“(2) धन संबंधी वाद में, न्यायालय अनिवार्यतः निरपवाद रूप से आदेश 21 नियम 11 का प्रयोग कर, मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान हेतु आज्ञाप्ति के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।”।
6. नियम 197 में, विद्यमान पैराग्राफ को उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के बाद निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—  
“(2) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत पद “ ..... निर्णीत-ऋणी के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से” को किसी अन्य व्यक्ति, जिससे वह हिस्सा, लाभ या संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, को सम्मिलित करने हेतु उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए।”।

- “(2) न्यायालय को, किसी संपत्ति के कब्जे के परिदान के संबंध में आज्ञाप्ति पारित करने के पूर्व आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज्ञाप्ति न केवल उस संपत्ति का स्पष्ट विवरण समाहित करे, बल्कि संपत्ति की स्थिति के संबंध में भी असंदिग्ध हो।”।
4. नियम 184 में, उप-नियम (1) के अंत में, शब्दों “वाद का निराकरण यथासम्भव शीघ्र हो जाए।” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
“वे प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक से छः माह के भीतर निराकृत हो जाएं, जिसे केवल लिखित में, ऐसे विलंब के कारणों को अभिलिखित करने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।”।
5. नियम 187 में, विद्यमान पैराग्राफ, उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—  
“(2) धन संबंधी वाद में, न्यायालय अनिवार्यतः निरपवाद रूप से आदेश 21 नियम 11 का प्रयोग कर, मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान हेतु आज्ञाप्ति के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।”।
6. नियम 197 में, विद्यमान पैराग्राफ को उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के बाद निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—  
“(2) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत पद “ ..... निर्णीत-ऋणी के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से” को किसी अन्य व्यक्ति, जिससे वह हिस्सा, लाभ या संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, को सम्मिलित करने हेतु उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए।”।



7. नियम 204 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

- "204-क (1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 या आदेश 21 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर यंत्रवत सूचना जारी नहीं करना चाहिए। अग्रेतर, न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन (आवेदनों) पर विचार करने से बचना चाहिए जिस पर पहले ही न्यायालय द्वारा वाद के न्यायनिर्णयन के समय विचार किया जा चुका हो या जो ऐसा विवाद्यक उठाता हो जो अन्यथा वाद के न्यायनिर्णयन के दौरान उठाया और न्यायनिर्णीत किया जा सकता था यदि आवेदक द्वारा सम्यक सावधानी बरती गई होती।
- (2) न्यायालय का निष्पादन की कार्यवाही के दौरान केवल आपवादिक व दुर्लभ मामलों में ही साक्ष्य लेने की अनुमति देनी चाहिए, जहां तथ्य का प्रश्न किसी अन्य त्वरित तरीके, जैसे कमिश्नर की नियुक्ति या शपथपत्र के साथ फोटो या वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मंगाने, का सहारा लेकर विनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- (3) न्यायालय को उपयुक्त मामलों में, जहां वह आपत्ति या प्रतिरोध या दावा तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण लगता है, आदेश 21 के नियम 98 के उप-नियम (2) का सहारा लेना चाहिए और साथ ही साथ धारा 35-क के अनुसार प्रतिकारात्मक खर्चे अनुदत्त करने चाहिए।"

8. नियम 232 में,-

- (1) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
- "(1) निष्पादन न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि पुलिस की सहायता के बिना डिक्री का निष्पादन संभव नहीं है, जिला

पुलिस अधीक्षक/ संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे कर्मचारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे सकता है जो डिक्री के निष्पादन की दिशा में कार्य कर रहे हैं।”।

(2) उप-नियम (2) में, “जिला पुलिस अधीक्षक” शब्दों के बाद चिन्ह व शब्द “/ संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी” अंतर्विष्ट किए जाएं, जहाँ कहीं भी वे आते हैं।

(3) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(3) यदि लोक सेवक के विरुद्ध उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी अपराध को न्यायालय के ज्ञान में लाया जाता है, तो उससे विधि के अनुसार कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।”।

9. नियम 243 के उप-नियम (1) में, अंत में, “सिविल प्रक्रिया संहिता” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“तथा उपयुक्त मामले, जहाँ कब्ज़ा विवादित नहीं है और न ही न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु वह तथ्य का प्रश्न है, तब संपत्ति के सटीक विवरण तथा स्थिति का आकलन करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है।”

10. नियम 276 में, अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“मामले के यथोचित न्यायनिर्णयन हेतु एक न्यायालय प्रापक को प्रश्नगत संपत्ति की स्थिति की निगरानी करने के लिए विधिक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।”

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल.

abalpur. the 19<sup>th</sup> May 2022

In exercise of powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No.19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 in pursuance to direction dated 22.04.2021 of the Hon'ble Supreme Court passed in Civil Appeal Nos.1659-1660 of 2021(@ Special Leave to Appeal Nos.7965-7966/2020), namely:-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Rule 138, in sub-rule (1), in the beginning, for the words, number and letters "The attention of presiding Judges is directed to the provisions of rule 1, Order X which are rarely observed", the following words, number and letters shall be substituted, namely:-

"In suits relating to delivery of possession, the court must examine the parties to the suit under Order X in relation to third party interest. The Presiding Officer shall comply with the provisions of Order X Rule 1 of the CPC."

2. In Rule 143,-

- (1) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(1-A) In suits relating to delivery of possession, the court must exercise the power under Order XI Rule 14 asking parties to disclose and produce documents, upon oath, which are in possession of the parties including

declaration pertaining to third party interest in such properties.”.

- (2) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2-A) After examination of parties under Order X or production of documents under Order XI or receipt of commission report, the Court must add all necessary or proper parties to the suit, so as to avoid multiplicity of proceedings and also make such joinder of cause of action in the same suit.”.

- (3) After sub-rule (4), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(5) In a suit for payment of money, before settlement of issues, the defendant may be required to disclose his assets on oath, to the extent that he is being made liable in a suit. The Court may further, at any stage, in appropriate cases during the pendency of suit, using powers under Section 151 CPC, demand security to ensure satisfaction of any decree.”.

3. In Rule 168, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2) The Court must, before passing the decree, pertaining to delivery of possession of a property ensure that the decree is unambiguous so as to not only contain clear description of the property but also having regard to the status of the property.”.

4. In Rule 184, in sub-rule (1) at the end, for the words “that cases are disposed of as speedily as possible.”, the following words shall be substituted, namely:-

“that execution cases are disposed of within six months from the date of filing, which may be extended only by recording reasons in writing for such delay.”.

5. In Rule 187, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2) In a money suit, the Court must invariably resort to Order XXI Rule 11, ensuring immediate execution of decree for payment of money on oral application.”.

6. In Rule 197, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2) Under section 60 of CPC the term “...in name of the judgment-debtor or by another person in trust for him or on his behalf” should be read liberally to incorporate any other person from whom he may have the ability to derive share, profit or property.”.

7. After Rule 204, the following rule shall be added, namely:-

“204-A. (1) The Court exercising jurisdiction under Section 47 or under Order XXI of CPC, must not issue notice on an application of third-party claiming rights in a mechanical manner. Further, the Court should refrain from entertaining any such application(s) that has already been considered by the Court while adjudicating the suit or

which raises any such issue which otherwise could have been raised and determined during adjudication of suit if due diligence was exercised by the applicant.

- (2) The Court should allow taking of evidence during the execution proceedings only in exceptional and rare cases where the question of fact could not be decided by resorting to any other expeditious method like appointment of Commissioner or calling for electronic materials including photographs or video with affidavits.
- (3) The Court must in appropriate cases where it finds the objection or resistance or claim to be frivolous or mala fide, resort to Sub-rule (2) of Rule 98 of Order XXI as well as grant compensatory costs in accordance with Section 35A.”.

8. In Rule 232,-

- (1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The Executing Court may on satisfaction of the fact that it is not possible to execute the decree without police assistance, direct the District Superintendent of Police/ S.H.O. of concerned Police Station to provide police assistance to such officials who are working towards execution of the decree.”.
- (2) In sub-rule (2), after the words “the District Superintendent of Police”, the symbol and words “/S.H.O. of concerned Police Station” shall be inserted, wherever they occur.

(3) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(3) In case an offence against the public servant while discharging his duties is brought to the knowledge of the Court, the same must be dealt with stringently in accordance with law.”.

9. In Rule 243, in sub-rule (1), at the end, after the words “Civil Procedure Code”, the following sentence shall be added, namely:-

“and in appropriate cases, where the possession is not in dispute and not a question of fact for adjudication before the Court, Commission may be issued to assess the accurate description and status of the property.”.

10. In Rule 276, at the end, the following sentence shall be added, namely:-

“A Court Receiver can be appointed to monitor the status of the property in question as *custodia legis* for proper adjudication of the matter.”.

By order of the Hon'ble Chief Justice,  
KRISHNAMURTY MISHRA. Registrar General.

## श्रम विभाग

## मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2022

अधिसूचना क्रमांक भसकम 4203.....मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना 2012 में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना तथा पश्चातवर्ती परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए एतद द्वारा "म.प्र. भवन संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना नीति 2022" मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिसूचित करता है:-

## (1) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना -

- (a) यह योजना नीति "म.प्र. भवन संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना नीति 2022" कहलाएगी।  
 (b) यह योजना नीति संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशाली होगी।  
 (c) यह योजना नीति मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

## (2) परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (a) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 से है।  
 (b) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002  
 (c) बोर्ड या मंडल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से है।  
 (d) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मंडल के सचिव से है।  
 (e) निर्माण श्रमिक कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से है।  
 (f) आश्रित से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार परिवार के सदस्य से है।  
 (i) पति अथवा पत्नी (यथास्थिति अनुसार)  
 (ii) अविवाहित पुत्र पुत्री, जिनकी आयु 16 से 45 वर्ष  
 (iii) आश्रित माता एवं पिता, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो  
 (g) इस योजना नीति में परिभाषित ना किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना नीति में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

## (3) उद्देश्य: इस योजना नीति का उद्देश्य अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका एच सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत वैध पंजीयन धारक श्रमिक तथा उसके परिवार के आश्रित सदस्यों के आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु -

- (a) नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (National Skill Qualification Framework) अंतर्गत राष्ट्रीय मानकों अनुसार गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण योजना संचालित करना है।  
 (b) मांग अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना जिनकी पूर्ती परंपरागत आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं है।

## (4) प्रशिक्षण कार्यक्रम: योजना नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु योजनाएं संचालित की जा सकेंगी:

- (a) लघु अवधि प्रशिक्षण (Short Term Training) - इसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा।



- (b) विशेष प्रशिक्षण (Special Training) - इसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को मण्डल द्वारा निर्धारित विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा।
- (c) रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (Recognition of Prior Learning)- इसके अंतर्गत हिताधिकारियों के अप्रमाणित कौशल को प्रमाणित किया जायेगा।  
सॉफ्ट (वैयक्तिक) कौशल (जिसमें कम्प्यूटर साक्षरता, भाषा और सेक्टर/टैड से संगत कार्यस्थल इन्टरपर्सनल कौशल शामिल है), कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग होंगे और सभी पाठ्यक्रम मॉड्यूलों में उपयुक्त रूप से समेकित किए जाएंगे।
- (5) **हितग्राही:** इस योजना नीति के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं हेतु वे सभी व्यक्ति पात्र हितग्राही होंगे जो कि -
- (a) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत वैध पंजीयन धारक श्रमिक (आयु 18 से 45 वर्ष तक) हैं अथवा मंडल अंतर्गत वैध पंजीयन धारक श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्य (आयु 16 वर्ष से 45 वर्ष) है तथा
- (b) वैध आधार कार्ड धारक एवं आधार से लिंक बैंक खाता धारक हैं तथा
- (c) NSQF पाठ्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक हैं। (रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के संबंध में लागू नहीं)
- (6) **प्रशिक्षण संस्थाएं:**
- (a) प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शासकीय, अर्ध-शासकीय तथा NSDC के पार्टनर के रूप में एमपैनल निजी प्रशिक्षण संस्थान सचिव, मंडल द्वारा आवश्यकता अनुसार चयनित किये जा सकेंगे।
- (b) शासकीय, अर्ध-शासकीय क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थानों का चयन एवं लक्ष्य निर्धारण सचिव, मंडल द्वारा जारी EOI/ITP/RFP के आधार पर किया जाएगा।
- (c) निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थानों का चयन एवं लक्ष्य निर्धारण अनिवार्य रूप से RFP जारी कर किया जाएगा।
- (d) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे जिनके लिए रोजगार प्रदायकर्ता सुनिश्चित रोजगार देने के लिए अनुबंध करेंगे।
- (e) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं को आबंटित हिताधिकारी लक्ष्य किसी अन्य संस्थान को Sublet, Subcontract अथवा फ्रैंचाइज़ी नहीं किया जा सकेगा।
- (7) **प्रशिक्षण ट्रेड एवं प्रशिक्षणार्थी संख्या:** NSQF के तहत निर्धारित पाठ्यक्रमों के Qualification Packs (QPs), NCVET (National Council for Vocational Education and Training) के National Qualification Register पोर्टल (nqr.gov.in) पर उपलब्ध हैं। संस्थानों द्वारा उक्त QPs का उपयोग (विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पर लागू नहीं) किया जायेगा। सचिव, मंडल द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता अनुसार कौशल प्रशिक्षण योजना हेतु जिलावार प्रशिक्षण ट्रेड, प्रशिक्षणार्थी लक्ष्य तथा प्रशिक्षक संस्थाएं निर्धारित किये जायेंगे। प्रशिक्षण ट्रेड तथा प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं प्रशिक्षक संस्था को निर्धारित/परिवर्तित करने का अधिकार सचिव, मंडल को होगा।
- (8) **कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन:**
- (a) **योजना संचालन समिति (SIC):** प्रशिक्षण संस्थानों के चयन के लिए EOI/ITP/RFP निर्माण हेतु, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु, राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं योजना से सम्बंधित अन्य आवश्यक कार्य हेतु योजना संचालन समिति (SIC) का गठन किया जाएगा। इस समिति में आवश्यकतानुसार कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र, IT (Information Technology) एवं लेखा कार्य से सम्बंधित सदस्य सम्मिलित/नियुक्त किये जा सकेंगे।
- (b) कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन सचिव, मंडल द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक चरण की प्रगति की जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अद्यतन की जावेगी।
- (9) **कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का पर्यवेक्षण:** योजना का राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण योजना संचालन समिति द्वारा किया जाएगा एवं संभाग/जिला स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल पर एवं भौतिक रूप से पर्यवेक्षण सचिव, मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/संस्था द्वारा किया जा सकेगा। कौशल प्रशिक्षण योजना के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सुझाव अथवा दिशा-निर्देश लिखित में संबंधित संस्थान को दिए जा सकेंगे।

- (10) **वित्तीय प्रावधान:** योजना नीति अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार आवास/भोजन भत्ता और विशेष क्षेत्रों/विशेष समूहों हेतु अन्य भत्ते तथा प्रोत्साहन राशि इत्यादि का प्रावधान किया जा सकेगा एवं कौशल प्रशिक्षण योजना हेतु प्रशिक्षण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क तथा प्रमाणीकरण शुल्क का निर्धारण कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार की सामान्य मानदंड समिति द्वारा जारी सामान्य मानदंडों (Common Cost Norms) के अनुसार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अन्य अवयवों जैसे योजना का प्रचार-प्रसार, योजना संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण/उपयोग शुल्क, पोर्टल संचालन/परामर्श शुल्क, स्किल-गैप स्टडी एवं योजना संचालन समिति हेतु विषय-विशेषज्ञ की नियुक्ति इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार राशि प्रावधानित की जा सकेगी।
- (11) **मूल्यांकन:** योजना नीति अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का मूल्यांकन सचिव, मंडल द्वारा निर्धारित अंतराल पर मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की साधिकार समिति अथवा अन्य विशेषज्ञ संस्था से कराया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के लिये निर्धारित सेक्टर, पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणार्थी लक्ष्य, प्रशिक्षण संस्था, ऑनलाइन पोर्टल एवं विषय-विशेषज्ञों की संख्या इत्यादि का पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा।
- (12) **योजना नीति का क्रियान्वयन:** योजना नीति के क्रियान्वयन हेतु सचिव, मंडल द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष इस योजना नीति दस्तावेज में उल्लेखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यक्रमों का चयन किया जाकर कौशल प्रशिक्षण योजना एवं कार्ययोजना तैयार की जाएगी एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाकर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

संजय जैन,

सचिव,

म.प्र. भ.स.क.क.मंडल.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधि. क्रमांक-72-एफ-01-15-2018-18-3

भोपाल, दिनांक 3 जून 2022

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्: -

### संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 में,-

(1) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(घ) “निर्वाचन” से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका में स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन और उसमें सम्मिलित हैं, यथार्थि, किसी नगर पालिक निगम के महापौर या किसी नगर पालिका या नगर परिषद के पार्षद के संबंध में निर्वाचन।”।

(2) खण्ड (झ-1) विलोपित किया जाए।

2. नियम 21 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(क) किसी महापौर या वार्ड के पार्षद के स्थान के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से सातवें दिन की होगी या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा, जो सार्वजनिक अवकाश न हो।”।

3. नियम 25, में उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“नियम-25(1)- नियम-21 के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो व्यक्तिशः या अपने प्रस्तावक के द्वारा नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर को, सम्यक् रूप से पूर्ण विहित प्ररूप में भरा गया और अभ्यर्थी

द्वारा तथा प्रस्तावक के रूप में "महापौर" के निर्वाचन के मामले में, नगर पालिका के किसी वार्ड के मतदाता द्वारा और किसी वार्ड से पार्षद के निर्वाचन के मामले में उस वार्ड के किसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करेगा:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा।"।

4. नियम 26 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) किसी भी अभ्यर्थी को महापौर या पार्षद के स्थान के निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करते समय या उसके पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के पास निम्नांकित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दी हो, अर्थात्:-

(क) पार्षद के स्थान के लिए,-

(एक) नगर परिषद के मामले में राशि रुपये 1000/- की धनराशि ;

(दो) नगर पालिका के मामले में राशि रुपये 3000/- की धनराशि ;

(तीन) नगर पालिक निगम के मामले में राशि रुपये 5000/- की धनराशि ;

(ख) किसी नगर पालिक निगम के महापौर के स्थान के लिए- रुपये 20,000/- की धनराशि:

परंतु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उसे उपरोक्त राशि का केवल आधा भाग निक्षेप के रूप में जमा करना होगा।"।

5. नियम 33 में,-

(एक) उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;

(दो) उपनियम (2) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए।

6. नियम 34 में,-

(एक) उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;

(दो) उपनियम (2) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए।

7. नियम 35 में,—  
 (एक) उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;  
 (दो) उपनियम (2) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए।
8. नियम 36 में,—  
 (एक) उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;  
 (दो) उपनियम (2) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए,  
 (तीन) उपनियम (3) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;  
 (चार) उपनियम (5) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए।
9. नियम 37 में,—  
 (एक) उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;  
 (दो) उपनियम (2) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए;  
 (तीन) उपनियम (3) में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाए।
10. नियम 72 में, उपनियम (6) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
 "(क) नगरपालिका का नाम तथा उस पद की नामावली जिससे मतपत्र संबंधित है जैसे महापौर या पार्षद।"
11. अध्याय आठ—क में,—  
 (एक) पार्श्व—शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व—शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
 "महापौर को अपने पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में मतदान"  
 (दो) नियम 75—क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
 "75—क— महापौर को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी प्रक्रिया का प्रारंभ— यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, महापौर को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया तुरन्त आरंभ करेगा और उसे छः माह के भीतर पूरी करेगा।"
12. नियम 75—घ में शब्द अध्यक्ष का लोप किया जाए।
13. नियम 75—च में शब्द अध्यक्ष का लोप किया जाए।

14. नियम 75—छ में शब्द अध्यक्ष का लोप किया जाए।
15. नियम 75—झ में शब्द अध्यक्ष का लोप किया जाए।
16. नियम 75—ञ में शब्द अध्यक्ष का लोप किया जाए।
17. नियम 79—क के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“नगर पालिका के किसी निर्वाचित महापौर या पार्षद का स्थान, मृत्यु, अनर्हता, त्यागपत्र, बिना अनुमति अनुपस्थिति, निर्वाचन अपास्त किये जाने आदि किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर, यथास्थिति नगरपालिका का आयुक्त या मुख्य कार्यपालिक अधिकारी ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।”।

18. नियम 81 में,

(एक) विद्यमान पार्श्व—शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व—शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“ महापौर एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय एवं संपरीक्षा का प्रस्तुत किया जाना।”।

(दो) उप—नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“अभ्यर्थी जो महापौर एवं पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके स्वयं के नाम खाता खोलना अपेक्षित होगा, जिसमें निर्वाचन की प्राप्तियों एवं व्ययों के पूर्ण ब्यौरे नियत होंगे। खाते के ब्यौरे रिटर्निंग आफिसर को दिए जाएंगे।”।

(तीन) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम (3) स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(3) राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14—क की उप—धारा (3) के अधीन महापौर/पार्षद एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32—क की उप—धारा (3) के अधीन पार्षद

पद के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आदेश जारी करेगा और राजपत्र में उसको प्रकाशित करेगा। निर्वाचन व्यय लेखा में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जा सकें। ये विशिष्टियां आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से अनुपूरित होंगी।

19. नियम 82 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“82—महापौर एवं पार्षद के पद के लिए, अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखों का दाखिल किया जाना :— मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14—ख के अनुसार, महापौर/पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा—32 (ख) में अभ्यर्थी जो नगर पालिका में निर्वाचन पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष मतगणना की तारीख के लिए, निर्वाचन तारीख से 30 दिनों के भीतर उन्हें उनके लेखे एवं व्यय विवरण प्रस्तुत करने होंगे।”।

20. नियम 83 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 83 स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“83—महापौर/पार्षद पद के लिए, अभ्यर्थियों की निरर्हता.— कोई अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14—(ग) या मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अधीन महापौर एवं पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, महापौर या पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए निरर्ह होंगे, यदि वह उपरोक्त नियम 81 एवं 82 के अनुसार बिना किसी उचित कारण के निर्वाचन व्यय खाता प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तथा निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के लिए पार्षद के उक्त पद या पद का चुनाव लड़ने के लिए भी निरर्हित होंगे।”।

21. इन नियमों में संलग्न प्ररूप 2, 2(क), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(क), 18, 18(क), 19, 19(क), 19(ख), 19(ग), 19(घ), 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25, 26 तथा 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

## प्ररूप-2

## नियम-21 देखिए,

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

## पार्षद/महापौर के निर्वाचन की सूचना

क्रमांक .....मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं.....जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)..... इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के महापौर/पार्षदों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा, निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि :-

- (क) अनुसूची के कॉलम (2) में वह/वे स्थान विनिर्दिष्ट हैं जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होना है;
- (ख) पार्षद/पार्षदों के निर्वाचन के मामले में, सम्बन्धित वार्ड/वार्डों के क्रमांक, अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट हैं;
- (ग) अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) होगा,
- (घ) अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा,
- (ङ) अनुसूची के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (च) अनुसूची के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (छ) अनुसूची के कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय ही जिसके दौरान मतदान होगा, मतदान की तारीख और समय होगा;
- (ज) अनुसूची के कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, ही मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा।

स्थान.....

तारीख.....

.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

नाम.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.



## अनुसूची

नगरपालिका का नाम	पद/पदों का विवरण जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होगा यथा महापौर/पार्षद	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के निर्वाचन के लिए)	रिटनिंग आफिसर (नगरपालिका) का नाम तथा पद	नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय	अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	वह तारीख तथा समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान.....

तारीख.....

.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

नाम.....

सील.....

प्र रूप-2-क

(नियम-22-(क) देखिए.)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

## सूचना

विषय-स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-22-(क) के अनुसरण में, एतद्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के महापौर/पार्षद के जिस स्थान/जिन स्थानों के लिए निर्वाचन होना है, उसके/उनके आरक्षण की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है :-

## तालिका

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा महापौर/पार्षद)	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के निर्वाचन के लिए)	आरक्षण की स्थिति (यथा अनु. जाति/अनु.जाति-महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति-महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य-महिला)
(1)	(2)	(3)

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला.....

नाम.....



## नगरपालिका निर्वाचन

प्ररूप-3

(नियम-24(2) देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

में प्रस्तावक, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :-

## निर्वाचन के पद का विवरण

जिला		अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया स्टाम्प आकार का फोटो (2 से.मी. x 2.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान
'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम		
'पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	महापौर/पार्षद	
पार्षद के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बंधित वार्ड का क्रमांक		

## अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	'लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			
5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण				
	नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जहां अभ्यर्थी का नाम दर्ज है।	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक जहां अभ्यर्थी का नाम दर्ज है।	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	

## प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)			
7.	'लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			
11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण				
	नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जहां प्रस्तावक का नाम दर्ज है।	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक	

\*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम

## अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की राग्गति

में ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्गति देता/देती हूँ और गेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ

निम्नानुसार है :-

12.	जन्मतिथि								
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति अथवा वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)								
15.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में जाति का नाम								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है								
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	1.							
		2.							
		3.							
19.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)								
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में								
21.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मे उपयुक्त नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के महापौर/पार्षद के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-24(क) के अधीन आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियाँ, दायित्वो तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के अधीन प्ररूप-8	
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के अधीन प्ररूप-9	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.	
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.	
6.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.	
9.	अन्य -	
10.	अन्य -	

लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये.

राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्भुल कॉलम में 'निर्दलीय' अंकित कीजिए.

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है, (कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है.)

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-24(क) के अधीन आपराधिक पूर्ववृत्त, आरिक्तयो, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अधीन प्ररूप-8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संबीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है	
6.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत् कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संबीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संबीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुदित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य -			
10.	अन्य -			

जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के हस्ताक्षर

नाम

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय  
मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-28 के अनुसार कर  
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ. -- (")

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर  
पालिका) के हस्ताक्षर

नाम

सील

“यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जायें.

अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1	नामनिर्देशन का क्रमक		
2	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5	अभ्यर्थी का नाम		
6	नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		
7	पद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है (साम्बन्ध की स्थिति में वार्ड क्रमांक भी अंकित किया जाये)		
8	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-24(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियो, दायित्वो तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-8		नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-9		नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.		सवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	'मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाणपत्र.		सवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
7	'मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत नगरपालिका नियम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाणपत्र.		संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ		नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
9.	अन्य -			
10.	अन्य -			

\*जा लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के हस्ताक्षर

नाम  
सील

परिच्छेद 4

(नियम-27 देखिए.)

नाम निर्देशन की सूचना

(नगर पालिक निगम के महापौर का निर्वाचन)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नाम निर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं :-

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	अभ्यर्थी की आयु (4)	पता (5)	दल से सम्बद्धता (6)
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------	---------------------------

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये जातियों/जनजातियों या अन्य वर्गों की विशिष्टियां (7)	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक (भाग अनुक्रमांक..... क्रमांक.....) (8)	प्रस्तावक का नाम (9)	मतदाता सूची में प्रस्तावक का क्रमांक (भाग अनुक्रमांक..... क्रमांक.....) (10)
--	--	----------------------------	--

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.



## प्ररूप-5

(नियम-28(8) देखिए.)

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

(नगर पालिक निगम के महापौर का निर्वाचन)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-6

(नियम-29(1) देखिए.)

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

## (नगर पालिक निगम के महापौर का निर्वाचन)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....  
.....से पार्श्व का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

मैं, ..... जो कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में विधिमान्य: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ,  
एतद्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ,

02

तारीख ..... को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत किया गया/किए गए नामनिर्देशन 'पत्र/पत्रों  
की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो 'रसीद/रसीदे दी गई थी वे इसके साथ मूल रूप से संलग्न हैं

स्थान.....

तारीख.....

विधिमान्य: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी  
के हस्ताक्षर

यह सूचना.....(नाम) के द्वारा जो' ..... है: (तारीख).....  
..... को .....(बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई थी.

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
के हस्ताक्षर

नाम.....  
सील.....

अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद  
(आवेदन परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

श्री.....द्वारा, जो कि 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका  
परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्श्व के निर्वाचन में विधिमान्य  
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन.....(') द्वारा तारीख.....  
को .....(बजे) मुझे मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
के हस्ताक्षर

नाम.....  
सील.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

"यहां नीचे लिखे विकल्पों में से एक समुचित विकल्प अंतस्थापित करें (1) अभ्यर्थी, (2) अभ्यर्थी का प्रस्तावक, (3) अभ्यर्थी  
का निर्वाचन अभिकर्ता

## प्ररूप-7

(नियम-29 (4) देखिए.)

अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना  
(नगरपालिका निगम के महापौर का निर्वाचन)

'नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमाम्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली हैं :-

विधिमाम्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का नाम (1)	विधिमाम्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का पता (2)	टिप्पणियां (3)
1.		
2.		
3.		

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-8

(नियम-31 (2) देखिए.)

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के सम्बन्ध में सूचना प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

जिला.....

विषय:- 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..... जिला.....  
के महापौर/पार्षद का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नाम,

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि ऊपर वर्णित आगामी नगरपालिका निर्वाचन/निर्वाचनों में.....(दल) द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के रूप में खड़े किए गए हैं :-

पद का विवरण पार्षद	वार्ड का क्रमांक अंकों में (2)	शब्दों में (3)	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम (4)	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम (5)
-----------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------------	--

अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक का पता (6)	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का नाम (जो अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम संवीक्षा में प्रतिक्षेपित होने पर या उसके लड़ने से हट जाने पर अभ्यर्थी के स्थान पर आएगा) (7)	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम (8)	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का डाक का पता (9)
---	--	---	--

भवदीय,

स्थान.....

तारीख.....

(दल की मोहर)

हस्ताक्षर  
(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत  
पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)  
नाम.....

प्रतिलिपि:-

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)

जिला..... की ओर सूचनार्थ.

स्थान.....

तारीख.....

(दल की मोहर)

हस्ताक्षर  
(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत  
पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)  
नाम.....

\*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-9

(नियम-31 (2) (चार) देखिए.)

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना  
.....दल मध्यप्रदेश

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

जिला.....

विषय:- 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....जिला.....  
के महापौर/पार्षद् का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने के लिए पदधारियों को प्राधिकृत किया जाना.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा यह सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में इस दल द्वारा जो (मध्यप्रदेश राज्य में एक) राष्ट्रीय दल/राज्य दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नाम संसूचित करने के लिए इस दल द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :-

नामों की संसूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम	दल की जिला इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम	जिला/जिले जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
(1)	(2)	(3)

02. ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया/किये गये/है/हैं, के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं :-

नाम	हस्ताक्षर
1. श्री.....	1. ....
2. श्री.....	2. ....
3. श्री.....	3. ....
स्थान.....	भवदीय,
तारीख:..... (दल की मोहर)	हस्ताक्षर.....
	अध्यक्ष/सचिव
	दल का नाम.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-10

(नियम-32 देखिए.)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची  
(नगर पालिक निगम के महापौर का निर्वाचन)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता	आवंटित प्रतीक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-11

(नियम-33 (1) देखिए.)

निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

मैं.....निवासी.....जो ऊपर वर्णित  
 निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा श्री.....निवासी.....  
 को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ,

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम.....

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ,

स्थान.....

तारीख.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

अनुमोदित

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-12

(नियम-34 (1) देखिए.)

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

मैं, ..... जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, ऊपर वर्णित  
 निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती.....पता.  
 .....को मतदान केन्द्र क्रमांक.....(मतदान के लिये नियत स्थान),  
 .....में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त  
 करता/करती हूँ

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ

स्थान.....

तारीख.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मतदान अभिकर्ता की घोषणा  
 (पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः  
 निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई  
 कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

जाँ विकल्प चिह्न न हो उसे काट दीजिए.



## प्ररूप-13

(नियम-35 (1) देखिए.)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
के वार्ड क्रमांक..... से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

मैं..... जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, ऊपर वर्णित  
निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा श्री/कु./श्रीमती.....  
पता..... को (गणना के लिये नियत स्थान).....  
पर होने वाली मतों की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त  
करता/करती हूँ.

स्थान.....

तारीख.....

.....

'अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम.....

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ.

स्थान.....

तारीख.....

.....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम.....

गणन अभिकर्ता की घोषणा  
(रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः  
निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई  
कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर  
नाम.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-14

(नियम-39 देखिए,)

निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(नगर पालिक निगम के महापौर का निर्वाचन)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 39 के उपनियम (1) के अनुसरण में,  
 मैं घोषित करता हूँ कि :-'

.....नाम

.....पता

'जो (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम).....द्वारा खड़े किये  
 गए/खड़ी की गई, ऊपर वर्णित निर्वाचन में महापौर/पार्षद के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए  
 हैं.

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)  
 के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.  
 "यदि अनावश्यक हो तो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-15

(नियम-49 (2) (ग) देखिए.)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

प्रविष्टि का क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपित व्यक्ति	पहचानकर्ता यदि कोई हो का नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-16

(नियम-52 (1) देखिए.)

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा-पत्र

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

मैं, .....पिता.....आयु.....  
 निवासी.....पता.....  
 .....

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैंने आज तारीख.....को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.
- (ख) मैं, श्री/कु./श्रीमती.....जो मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक.....के क्रमांक.....पर दर्ज है के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान.....

तारीख.....

(साथी के हस्ताक्षर)

नाम.....

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

'जा विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-17

(नियम-54 (2) देखिए.)

## निविदत्त मतों की सूची

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

क्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		मतदाता का पता (5)	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक (6)
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक (3)	मतदाता का क्रमांक (4)		

व्यक्ति को, जिसने मत डाल दिया,  
 जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक  
 (7)

मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर  
 या अंगूठे का निशान  
 (8)

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
 नाम.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-17-क

(नियम-63 ट (1) (क) देखिए.)

मतदाता रजिस्टर

(जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से निर्वाचन कराया जाएगा)

'नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्.....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर / पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	मतदाता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम.....

प्ररूप-18  
(नियम-57 देखिए.)  
भाग-1 - मतपत्र लेखा

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक...  
.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.  
मतदान केन्द्र का क्रमांक.....तथा नाम.....

	अनुक्रमांक		कुल संख्या
	कहाँ से	कहाँ तक	
1. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या			
2. उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या			
3. मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्र (1-2 = 3)			
4. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र :-			
(क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
(ख) निविदित मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
(ग) रद्द किये गये मतपत्र			
योग (क+ख+ग)			
5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र			
(3-4=5)			
(अनुक्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है)			

स्थान.....  
तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम.....

भाग-2 - प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या.....
2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 5 में दर्शायी गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो.....

तारीख.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर  
नाम.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर  
नाम.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-18 क  
(नियम-63 थ देखिए,  
भाग-1-अभिलिखित मतों का लेखा  
(जहां ई.व्ही.एम. से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम.....नियंत्रण यूनिट क्र.....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक मतदान यूनिट क्र 1.....

2.....

प्रिन्टर क्र (यदि प्रयुक्त हुआ है).. ..

डी.एम.एम. का संख्यांक.....

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित वोटर्स की संख्या
4. नियम 63ठ के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2-3-4=5)
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

क्रम संख्या

से.....तक

कुल.....

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापिस लिए गए.....

7. कागज की सीलों का लेखा

- |  |                         |                             |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें.              | कुल संख्या.....         | मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर |
|  | क्रम संख्या.....से..... | तक 1.....                   |
| 2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें                            | कुल संख्या.....         | 2.....                      |
|  | क्रम संख्या.....से..... | तक 3.....                   |
| 3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई प्रयुक्त कागज की सीलें. | कुल संख्या.....         | 4.....                      |
|  | क्रम संख्या.....से..... | तक 5.....                   |
| 4. नष्ट हुई कागज की सीलें यदि कोई हों :                  | कुल संख्या .....        | 6.....                      |
|  | क्रम संख्या .....       | से..... तक                  |

तारीख.....

स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक.....



## भाग-2-प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई ई.व्ही.एम. में पाये गये मतों की कुल संख्या.....
2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 3 में दर्शायी गई ई.व्ही.एम. में पाए गए मतों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो.....

स्थान.....

तारीख.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के  
हस्ताक्षर

## प्ररूप-19

(नियम-63 (2) देखिए.)

## निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये आवेदन

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका),

जिला.....

महोदय,

मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपना मत देना चाहता/चाहती हूँ मुझे 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....के मतदान केन्द्र क्रमांक.....पर निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है.

2. मेरा नाम ऊपर वर्णित 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक.....के क्रमांक.....पर प्रविष्टि है.

3. निवेदन है कि मुझे एक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजें, ताकि मैं अपना मत दे सकूँ

पता :

.....  
.....  
.....

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थान.....

तारीख.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-(क)  
(नियम-63 (4)(क) देखिए.)

लिफाफा-क

(क)	गणना के पूर्व न खोला जाए
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् का निर्वाचन.	
निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र	
मतपत्र क्रमांक.....	

जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-(ख)  
(नियम-63 (4)(ख) देखिए.)

लिफाफा-ख

(ख)

गणना पूर्व न खोला जाए

निर्वाचन तत्काल

\*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के  
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....  
जिला.....

.....  
भेजने वाले के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-(ग)  
(नियम-63 (4)(ग) देखिए.)

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
.....के  
वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में वह मतदाता हूँ जिसे क्रमांक.  
..... का निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया गया है.

तारीख.....

.....

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

.....

हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन

ऊपर वर्णित घोषणा पर श्री/कु./श्रीमती.....(मतदाता) ने, जिसे मैं,  
स्वयं, जानता/जानती हूँ/जिसे (पहचानने वाले) श्री/कु./श्रीमती.....ने, जिसे मैं,  
स्वयं जानता/जानती हूँ, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं.

.....

यदि कोई पहचानने वाला है तो हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

तारीख.....

.....

अभिप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

.....

तारीख.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-(घ)  
(नियम-63 (4)(घ) देखिए.)

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
.....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

1. इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे उक्त वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने इस प्रयोजन से रखे गए स्थान पर स्पष्ट रूप से ✓ या x या अन्य रीति से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें, जिससे स्पष्ट और बिना किसी संदेह के परे यह उपदर्शित हो जाए कि आप किसी अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं। यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह हो कि आपने मत किस अभ्यर्थी को दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा।
2. मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने के अपेक्षित चिन्ह से भिन्न किसी भी प्रकार के न तो हस्ताक्षर करें न कोई शब्द लिखें, न कोई चिन्ह या संकेत लगाए और न कोई बात लिखें।
3. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिन्हित (प्ररूप-19-क में) छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बंद कर दें और उसे सील लगाकर या अन्यथा सुरक्षित रूप से बंद कर दें।
4. फिर आप प्ररूप-19-ग में इसके साथ भेजी गई घोषणा पर नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करा लें--

क. यदि आप शासकीय सेवक हैं या किसी नगरपालिका अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं तो जहां आप कार्यरत हैं उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख।

ख. कोई राजपत्रित अधिकारी, जो आपको जानता है या उस मतदान केन्द्र का जिस पर आप निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ हैं पीठासीन अधिकारी।

ग. नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी।

आप यह घोषणा ऊपर वर्णित विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के पास ले जाएं और आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर करें, यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करके घोषणा आपको लौटा देगा, आप अपना मतपत्र अभिप्रमाणन अधिकारी को नहीं दिखाए और न ही उसे बताएं कि आपने किस को मत दिया है।

5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप-19-ग में घोषणा और साथ ही "क" चिह्नित (प्ररूप-19-क) में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिह्नित (प्ररूप-19-ख में) बड़े लिफाफे में रखें. बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) को डाक से या संदेश वाहक के माफत भेजे अथवा उसे व्यक्तिशः परिदत्त करे. कृपया "ख" चिह्नित (प्ररूप-19-ख में) बड़े लिफाफे को रिटर्निंग आफिसर को भेजने या सौंपने के पूर्व उस अंकित प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें.
6. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना हेतु नियत तारीख और समय 'पर अर्थात् तारीख ..... को पूर्वाह्न/अपराह्न.....बजे पूर्व उक्त लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए.
7. कृपया यह भी ध्यान रखे कि :-
  1. यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति में अभिप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा.
  2. यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास नियत तारीख और समय के पश्चात् पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.

प्ररूप-20

(नियम-66 (10) देखिए)

## निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

.....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (क) विधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....  
 (ख) अविधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....  
 (ग) प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या.....

स्थान.....

तारीख.....

सिटनिंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.



प्ररूप-21  
(नियम-69 (2) देखिए.)

गणना का परिणाम

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....  
.....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....  
(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....  
(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या.....

.....  
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....

स्थान.....

.....  
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

तारीख.....

नाम.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-21 (क)  
(नियम-69 (ख) देखिए)

गणना का परिणाम

(जहां ई.व्ही.एम. से निर्वाचन कराया जाएगा)

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

.....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

(पार्षद के लिये पृथक-पृथक भरना है.)

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
6.	.....	.....

2. (क) अन्डर/नो वोटों की संख्या.....

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या.....

(ग) इनमें से कोई नहीं (नोटा).....

.....  
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर  
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन  
अभिकर्ता का नाम  
पूरे हस्ताक्षर

स्थान.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

तारीख.....

नाम.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-22

(नियम-69 (3) देखिए.)

अन्तिम परिणाम पत्र

'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के  
वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद का निर्वाचन.

अन्तिम परिणाम पत्र

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की मतदान केन्द्रवार संख्या						महायोग
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
			मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....  
 (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....  
 (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या.....  
 (चार) विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....  
 (पांच) अविधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....  
 (छः) डाले गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....  
 (सात) इनमें से कोई नहीं (नोटा).....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर  
नाम.....

स्थान.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

तारीख.....

नाम.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

## प्ररूप-23

(नियम-74 देखिए.)

## निर्वाचन की घोषणा सह-विवरणी

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....  
 .....के

वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद् का निर्वाचन.

## (1) निर्वाचन की विवरणी

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	दल से सम्बद्धता	प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

मतदाताओं की कुल संख्या.....

डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

इनमें से कोई नहीं (नोटा) को प्राप्त मतों की संख्या.....

प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या.....

निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

## (2) विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि :-

.....(नाम)

.....(पता)

सम्यकरूप से निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

सील.....

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

टिप्पणी-किन्ही अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाने के मामले में नियम-73 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

## प्ररूप-24

(नियम-75 देखिए.)

## निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मैं, 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर परिषद् .....  
 जिला.....के रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) एतद्वारा प्रमाणित  
 करता हूँ कि मैंने.....के .....(माह) की तारीख.....  
 को यह घोषित कर दिया है कि श्री/श्रीमती/कु. ....  
 पता.....जो  
 (मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नाम).....द्वारा  
 खड़े किए गए/की गई है, 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .....  
 .....के वार्ड क्रमांक.....से महापौर/पार्षद के रूप में सम्यक् रूप  
 से निर्वाचित हो गए/गई हैं और इनके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाण-पत्र  
 प्रदान किया है।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

सील.....

'जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-25

(नियम 75-(ग) देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ), जिला.....

महापौर को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना

क्रमांक .... मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा ( 2 )/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिक निगम महापौर श्री/श्रीमती..... को वापस बुलाने के संबंध में मतदान कराने का संदर्भ इस आधार पर किया है कि तीन-चौथाई पार्षदों द्वारा वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं :

यतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा (3), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उक्त महापौर को वापस बुलाने के संबंध में नियमानुसार मतदान की व्यवस्था करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे निदेश दिया गया है :

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, ..... जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला. .... नगरपालिक निगम ..... के उक्त महापौर श्री/श्रीमती..... को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के लिए एतद्वारा निम्नानुसार सूचना देता हूँ

(एक) मतदान दिनांक ..... को .....बजे पूर्वाह्न से ..... बजे अपराह्न तक होगा ।

(दो) मतगणना दिनांक..... को स्थान .....पर .....बजे पूर्वाह्न से ..... अपराह्न तक होगी,

(तीन) इस मतदान के लिए श्री..... कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रिटर्निंग ऑफिसर होंगे,

स्थान - .....

दिनांक-

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला .....

नाम .....

## प्ररूप-26

(नियम 75-(च) देखिए)

महापौर को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नगर पालिक निगम .....के महापौर श्री/श्रीमती .....  
 .....को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नाम (1)	मतदान का विकल्प (2)	प्रतीक (3)
.....	क- वापस बुलाने के लिए (पद रिक्ति के लिए) ख- वापस बुलाने के विरुद्ध (पद पर पूर्ववत् बने रहने के लिए)	..... .....

स्थान -

रिटर्निंग ऑफिसर ( नगरपालिका )

दिनांक -

नाम .....

प्ररूप-27

(नियम 75-(ज) देखिए)

महापौर को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के परिणाम की घोषणा

नगरपालिक निगम ..... के महापौर श्री/श्रीमती..... को वापस बुलाने के संबंध में दिनांक ..... को हुए मतदान में कुल..... मत पड़े, जिसमें से..... मत वापस बुलाने के पक्ष में तथा ..... मत वापस बुलाने के विरुद्ध थे, तथा ..... मत अवैध पाये गये थे।

अतएव, मैं .....रिटर्निंग ऑफिसर, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ कि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक/आधे से कम मतदाताओं ने महापौर को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया है जिसके परिणामस्वरूप महापौर, पदमुक्त माना जायेगा/पद पूर्ववत् धारण करता रहेगा।

स्थान -

हस्ताक्षर ( रिटर्निंग ऑफिसर ).....

दिनांक-

नाम .....

मुहर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.